जून 2022
खंड - XXXVIII | अंक - II

एक्ज़िमिअस: निर्यात लाभ

इस अंक में

- भारत से परियोजना निर्यातों को बढ़ाना
- भारत और मध्य एशिया को फिर से जोड़ना
- मुक्त व्यापार समझौतों में भारत की भागीदारी
- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के व्यापार और निवेश संबंध
- वित्त और विकास पर निबंध

तिमाही प्रकाशन

इंडिया एक्ज़िम बैंक

केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई - 400 005.
फोनः 022 2217 2600
ईमेलः ccg@eximbankindia.in
www.eximbankindia.in
www.eximmitra.in

भारत से परियोजना निर्यातों को बढ़ाना

परियोजना निर्यातों में आस्थगित भुगतान शर्तों पर इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात और विदेशों में टर्नकी परियोजनाओं तथा सिविल निर्माण कॉन्ट्रैक्टों पर काम करना शामिल है। परियोजनाओं को विभिन्न तरीकों से वित्तपोषण प्रदान किया जाता है, जिसमें संप्रभु, बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी), विकास वित्तपोषण संस्थान (डीएफआई), और अन्य देशों में सरकारों और/या सरकार समर्थित संस्थानों द्वारा वित्तपोषण शामिल है।

एमडीबी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं दुनियाभर में किए गए कुल परियोजना निर्यातों के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंकों से जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार, भारतीय कंपनियों ने विश्व बैंक (डब्ल्यूबी), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), अफ्रीकी विकास बैंक समूह (एएफडीबी), अंतर-अमेरिकी विकास बैंक (आईडीबी), और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (ईबीआरडी) द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में 2017-2021 के दौरान 26.1 बिलियन यूएस डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। इन परियोजनाओं का उल्लेखनीय हिस्सा अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से हासिल किया गया है। दक्षिण एशिया, उप-सहारा अफ्रीका और मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों में, भारत शीर्ष आपूर्तिकर्ता देशों में से एक है। भारतीय कॉन्ट्रैक्टर एमडीबी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में सभी क्षेत्रों में ऊर्जा, परिवहन और जल आपूर्ति/स्वच्छता क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, लेकिन उन्हें इनमें से हर क्षेत्र में जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से चीन से।

परियोजना निर्यात बढ़ाने के लिए प्रमुख रणनीतियां

निर्यात ऋण एजेंसियों को सुदृढ़ बनानाः प्रतिस्पर्धी वित्त प्रदान करना परियोजना निर्यातों की सफलता के प्रमुख कारकों में से एक है। परियोजनाओं के लिए कम ब्याज, लंबी अवधि की वित्तीय सहायता देने में निर्यात ऋण एजेंसियों (ईसीए) की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत में इन संस्थाओं को सुदृढ़ करने की जरूरत है।

- ***विनियामक सुगमता और संसाधन जुटाने के लिए सहायताः*** इंडिया एक्ज़िम बैंक अपनी निवल स्वाधिकृत निधि के 10 गुना तक संसाधन जुटा सकता है। यह सीमा भारत में वाणिज्यिक बैंकों के बराबर है। हालांकि, दुनिया भर में अन्य प्रमुख निर्यात ऋण एजेंसियों द्वारा इस लीवरेज नियम का पालन नहीं किया जाता है। इसलिए, आवश्यकता अनुसार, बोर्ड स्तर के अनुमोदन के साथ, इस लीवरेज अनुपात को बढ़ाकर 20 गुना तक किया जा सकता है। साथ ही, एक शीर्ष संस्था के रूप में इंडिया एक्ज़िम बैंक के पास अनिवार्य रूप से एक्सपोज़र संकेंद्रण होना चाहिए। इस संदर्भ में, एकल उधारकर्ता और उधारकर्ता समूह के लिए विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमाओं में ढील देने पर विचार किया जा सकता है। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (बीसी-एनईआईए) के अंतर्गत क्रेता ऋण के लिए आरबीआई की आईरैक मानदंडों में भी ढील दी जा सकती है। इसके अलावा, इंडिया एक्ज़िम बैंक को अमेरिका, कनाडा, और जापान की निर्यात ऋण एजेंसियों की तरह

आयकर से छूट दी जा सकती है। इससे बैंक अपने पूरे लाभ का इस्तेमाल अपने परिचालनों और ऋणों को बढ़ाने के लिए कर सकता है।

इंडिया एक्ज़िम बैंक की विदेशी उधारियों पर विदहोल्डिंग टैक्स अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी ऋण पैकेज प्रदान करने की बैंक की क्षमता को प्रभावित करता है। भारत सरकार इंडिया एक्ज़िम बैंक की विदेशी उधारियों पर विदहोल्डिंग टैक्स से छूट देने पर विचार कर सकती है। हाल ही में स्थापित नैशनल बैंक फॉर फायनैंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए उधारियों पर भारत सरकार की गारंटी को इंडिया एक्ज़िम बैंक की विदेशी उधारियों के लिए भी गारंटी के रूप में माना जा सकता है।

- ***रियायती उधार के दायरे का विस्तार:*** विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर संरचित लंबी अवधि और अधिक स्थगन अवधि वाले ऋणों की आवश्यकता होती है। आईएमएफ 'ऋण सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क' के अनुसार कुछ मामलों में, विशेष रूप से अत्यधिक ऋणग्रस्त गरीब देशों (एचआईपीसी) को न्यूनतम 35% के रियायती स्तर के साथ ऋण देना जरूरी है। हालांकि, ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जाने वाले अधिकांश ऋण आईएमएफ की इस शर्त को पूरा करता है, किन्तु बीसी-एनईआईए और रियायती वित्तपोषण योजना जैसे दूसरे कार्यक्रम इस न्यूनतम अनुदान शर्त को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए उन ऋणों को रियायती ऋण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। रियायत के दायरे को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार इंडिया एक्ज़िम बैंक के क्रेता ऋण कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान किए गए परियोजना निर्यातों के लिए ब्याज अनुदान देने पर विचार कर सकती है। इस तरह का कदम भारत की स्थिति को विकास भागीदार के रूप में मजबूत करेगा और विभिन्न बाजारों में परियोजना निर्यातकों की मूल्य स्पर्धात्मकता में भी सुधार होगा। इसमें मध्यम आय वाले देश भी शामिल हो सकते हैं, जिन तक ऋण-व्यवस्था के तहत दी गई सहायता के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता है।
- ***विदेशी मुद्रा में जोखिम कम करने वाले इंस्ट्रूमेंट:*** भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के मानदंडों के अनुसार, ईसीजीसी लिमिटेड को विदेशी मुद्रा में बीमा कवर देने की अनुमति नहीं है। विदेशी मुद्रा में बीमा कवर देने की सुविधा, निर्यातकों के लिए लेन-देन लागत को काफी कम कर सकती है। इसलिए, बीमा कवर विदेशी मुद्रा में भी उपलब्ध होना चाहिए। बीसी-एनईआईए के तहत विदेशी मुद्रा में कवर देने के लिए इरडा द्वारा ईसीजीसी लिमिटेड को विशेष छूट देने की आवश्यकता है। ऐसे विदेशी मुद्रा कवर के लिए आरबीआई द्वारा नियामक पर्यवेक्षण प्रदान किया जा सकता है, जो देश में निर्यात ऋण के लिए भी नियामक है।

न्यूनतम अपेक्षित स्थानीय सामग्री की समीक्षा करना: इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कई भारतीय परियोजना निर्यातकों का मानना है कि ऋण-व्यवस्था के तहत निर्धारित न्यूनतम सामग्री की आवश्यकता को पूरा करना चुनौती हो सकती है। विशेष रूप से, दूर के बाजारों में सिविल निर्माण परियोजनाओं में। हो सकता है कि कुछ ईसीए द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप घरेलू सामग्री की आवश्यकता में ढील देना सही न हो। लेकिन परियोजना निर्यात के कुछ क्षेत्रों और चुनिंदा भौगोलिक क्षेत्रों में, न्यूनतम सामग्री आवश्यकता की गणना के लिए एक मूल्यवर्धित दृष्टिकोण के बारे में सोचा जा सकता है। इसके अलावा, सिविल निर्माण परियोजनाओं में, भारत सरकार द्वारा घरेलू सामग्री की आवश्यकता में छूट पर विचार किया जा सकता है। लेकिन इस शर्त के साथ कि मुख्य कच्चे माल को परियोजना वाले देश से स्थानीय स्तर पर मिली छूट की सीमा तक लिया जाएगा। साथ ही, किसी तीसरे देश से कच्चे माल के आयात पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं।

परियोजना बाजारों में स्थानीय उपस्थिति, संयुक्त उद्यमों और कंसोर्शियम दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना: भारतीय परियोजना निर्यातकों के इंडिया एक्ज़िम बैंक के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि सभी निर्यातक, परियोजना वाले देशों में संयुक्त उद्यमों (जेवी) के माध्यम से सहयोग करने के लिए तैयार हैं और उनमें से लगभग 60% पहले से संयुक्त उद्यम में लगे हुए हैं। इनमें अधिकांश मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में हैं। बाजार में संयुक्त उद्यम बनाने के लिए भारतीय कंपनियों को सहायता और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। परियोजना वाले देश में स्थानीय उपस्थिति होने से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में सफलता मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। स्थानीय उपस्थिति से कंपनियों को राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के तहत कॉन्ट्रैक्टों के लिए बोली लगाने में भी मदद करती है। इसके अलावा, भारतीय कंपनियों को भी विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों के लिए बोली लगाने हेतु कंसोर्शियम दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नवगठित अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के चलते अफ्रीकी महाद्वीप में ऐसे अवसरों के बढ़ने की उम्मीद है।

एफटीए/आरटीए वार्ता में परियोजना निर्यातों को ध्यान में रखना: अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार करार / क्षेत्रीय व्यापार करार (एफटीए/आरटीए) वार्ताओं में परियोजना निर्यातों की संभावनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। गैर-टैरिफ बाधाएं जैसे कि उच्च वीजा शुल्क, परियोजना कार्यान्वयन के लिए लंबी अवधि के बहु-प्रवेश वीजा जारी न करना और कुछ बाजारों में प्रोफेशनलों को कमीशन करना चिंता का प्रमुख विषय है। एफटीए/आरटीए वार्ताओं में विदेशों में परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए सही व्यक्तियों की आवाजाही को सुगम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। साझेदार देशों के साथ इस तरह के समझौतों में प्राथमिकता के आधार पर परियोजनाओं को निष्पादित करने वाले भारतीय कॉन्ट्रैक्टों के कामगारों और अधिकारियों को वीजा देने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, इस संबंध में वीजा शुल्क और अवधि पारस्परिकता के सामान्य नियम के अनुसार भी हो सकता है।

काउंटर-ट्रेड व्यवस्था: काउंटरट्रेड, भारतीय परियोजना निर्यातकों के लिए समृद्ध संसाधनों के साथ उन नए भौगोलिक क्षेत्रों में एक प्रभावी बाजार विविधीकरण रणनीति के रूप में काम कर सकता है, जो जावक रेमिटैंस में प्रतिबंधों का सामना करते हैं। यह ऋण संकट के जोखिम वाले देशों में विकासात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण से जुड़े जोखिमों को कम करने का एक प्रभावी तरीका भी प्रदान करता है। भारत सरकार के विकास साझेदारी कार्यक्रमों में देय राशि की वसूली या भविष्य के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने की दृष्टि से काउंटरट्रेड रणनीति पर विचार किया जा सकता है।

खरीद के अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करना: एमडीबी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं से बनने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारतीय निर्यातकों को तैयार करने के लिए विस्तृत जागरूकता कार्यशालाओं के आयोजन की

आवश्यकता है। ये कार्यशालाएं निर्यातकों को उत्तरदायी बोलियां तैयार करने में प्रशिक्षित कर सकती हैं, उन्हें परियोजना देशों में विशिष्ट आवश्यकताओं (मानकों, विनियमों, तकनीकी विशेषताओं आदि) के बारे में अवगत करा सकती हैं और परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के लिए अधिक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कर सकती हैं। इंडिया एक्ज़िम बैंक पहले से ही एमडीबी के सहयोग से ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। उद्योग संघों, इंडिया एक्ज़िम बैंक, एमडीबी के निवासी मिशनों और अन्य प्रमुख हितधारकों के परामर्श से वाणिज्य विभाग द्वारा इस तरह के और कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

सह-वित्तपोषण/समानांतर वित्तपोषण: अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों जैसे एमडीबी, ईसीए और राष्ट्रीय डीएफआई के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सह-वित्तपोषण/समानांतर वित्तपोषण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बढ़ते बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ परियोजना वित्तपोषण क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ा सकता है। एमडीबी और अन्य ईसीए द्वारा सह-वित्तपोषण के माध्यम से एक्ज़िम बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में वित्तपोषण की कमी को पूरा करने पर विचार किया जा सकता है। एमडीबी और एक्ज़िम बैंक के बीच फंडिंग स्ट्रक्चर और फंड की लागत में अंतर को संरेखित कर, सह-वित्तपोषण / समानांतर वित्तपोषण दृष्टिकोण को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार के समर्थन की भी आवश्यकता होगी।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए जानकारियां साझा करना: पीपीपी के लिए भारत के अनुकूल परिवेश में परियोजना की तैयारी और क्षमता निर्माण पर बहुत ध्यान दिया गया है। इस समय भारत अन्य विकासशील देशों में पीपीपी परियोजनाओं के विकास में तकनीकी सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए सही स्थिति में है। भारत विशेष रूप से अफ्रीका में पीपीपी व्यवस्थाओं के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां साझा करने की दिशा में अपने प्रयास बढ़ा सकता है। इससे विकासशील देशों में बेहतर वित्तीय परिवेश तैयार होगा और साथ ही, भारतीय कंपनियों के लिए इन देशों में निवेश करने और कॉन्ट्रैक्ट निष्पादित करने के अधिक अवसर पैदा होंगे।

बैंकयोग्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए परियोजना तैयारी संबंधी सुविधाएं: बुनियादी ढांचागत निवेश के अंतर को कम करने के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करने में यह मुद्दा लंबे समय से एक बड़ी बाधा रहा है कि परियोजना वित्तपोषण के लिए पात्र है या नहीं। परियोजना की बैंक योग्यता बढ़ाने के लिए परियोजना तैयार करने की सुविधाओं को विकसित करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वर्तमान में, परियोजना तैयार करने की सुविधाओं में भारत की भागीदारी ज्यादातर परियोजना विकास गतिविधियों के शुरुआती चरणों तक ही सीमित है। तैयारी के बाद की गतिविधियों में जुड़ने और काम शुरू होने और उसके बाद के चरणों पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है।

संपोषी/नवीकरणीय क्षेत्र पर अधिक जोर : वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वहीं, भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन-III के दौरान भारत सरकार ने अफ्रीका में सौर परियोजनाओं के लिए 2 बिलियन यूएस डॉलर की रियायती ऋण-व्यवस्थाएं निर्धारित की थीं। हालांकि, भागीदार देशों द्वारा ऐसी ऋण-व्यवस्थाएं कम ही ली जा रही हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लागत स्पर्धात्मकता में सुधार करना महत्त्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस खंड से परियोजना निर्यात में वृद्धि के लिए अकेले वित्तपोषण से काम नहीं होगा। इसलिए, भारतीय कंपनियों को चीनी कंपनियों से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, घरेलू सौर पीवी निर्माताओं को भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे अक्षय ऊर्जा खंड में भारतीय परियोजना निर्यातकों की क्षमताओं में भी वृद्धि होगी।

छोटी कंपनियों के लिए सब-कॉन्ट्रैक्टिंग दृष्टिकोण : लघु और मध्यम उद्यम, प्रमुख यूरोपीय/ अमेरिकी/ जापानी कंपनियों से सब-कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर परियोजना निर्यातों में जुड़ सकते हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए, बहुपक्षीय विकास बैंकों के भारत में कार्यालय, एमडीबी में ईडी (भारत) का कार्यालय, विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ परियोजना निर्यातकों को ऐसे अवसरों के बारे में अग्रिम रूप से सूचित कर सकता है। छोटी कंपनियों को इन सब-कॉन्ट्रैक्ट अवसरों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं का अनुभव मिलेगा और उनकी क्षमताएं बढ़ेंगी और आने वाले समय में वे स्वतंत्र रूप से बोली लगाने के लिए भी सक्षम हो सकेंगी।

एसएमई भागीदारी को बढ़ाने के लिए पुल/पुश कार्यक्रम: ये संयुक्त वित्तपोषण कार्यक्रम हैं, जिसमें देशों का उद्देश्य यह रहता है कि वस्तुएं और सेवाएं उनके देश से ली जाएं। इसके लिए वे प्रमुख बहुराष्ट्रीय विनिर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और बदले में उनसे प्रतिबद्धता लेते हैं कि वे भविष्य में वस्तुएं और सेवाएं उन देशों से ही लेंगे। ये कार्यक्रम घरेलू आपूर्तिकर्ताओं और विदेशी खरीदारों को जोड़कर, वित्तपोषण को भी जोड़ते हैं। ईडीसी (कनाडा) और एसएसीई (इटली) सहित कई निर्यात ऋण एजेंसियों ने इस तरह की रणनीति को सफलतापूर्वक लागू किया है। भारत के लिए भी इसी तरह का कार्यक्रम विकसित किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल परियोजना निर्यात कॉन्ट्रैक्टों में छोटे कंपनियों को सब-कॉन्ट्रैक्टों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किया जा सकता है।

*05 मई, 2022 को नई दिल्ली में **"भारतीय परियोजना निर्यातकों के लिए वैश्विक अवसर बढ़ाना"** विषय पर आयोजित इंडिया एक्ज़िम बैंक के सम्मेलन में, माननीय वाणिज्य और उद्योग, कपड़ा, और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा 'भारत से परियोजना निर्यात: बदलते परिवेश में संभावनाओं का पता लगाना' विषयक इंडिया एक्ज़िम बैंक के अध्ययन का विमोचन किया गया।*

भारत और मध्य एशिया को फिर से जोड़ना

मध्य एशियाई गणराज्यों (सीएआर) में बंदरगाहविहीन पांच देश और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं - कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये सभी देश यूरोप और एशिया के बीच एक सेतु के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी देशों की सीमा एक-दूसरे से और सिर्फ तीन अन्य अर्थव्यवस्थाओं- रूस, चीन, और अफगानिस्तान से लगती है। इस वजह से इनका निर्यात दायरा बहुत छोटा है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और 2020 में इसकी संयुक्त जनसंख्या 74.8 मिलियन और सकल घरेलू उत्पाद 292.5 बिलियन यूएस डॉलर का रहा।

मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के व्यापार में रुझान

सीएआर, रणनीतिक हित की दृष्टि से भारत के लिए काफी महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। इसकी वजह है, इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज और हाइड्रोकार्बन भंडार और भूमि तथा समुद्री मार्गों के माध्यम से कई व्यापारिक परियोजनाओं के विकास की संभावनाएं। यह क्षेत्र, भारत के "विस्तारित पड़ोस" का हिस्सा होने के नाते, भारत की विदेश नीति में महत्त्वपूर्ण है।

सीएआर के साथ भारत के कुल व्यापार में तीन गुना से अधिक वृद्धि देखी गई है। यह वर्ष 2011 में 610.2 मिलियन यूएस डॉलर का था, जो 2020 में बढ़कर 1.9 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। इस क्षेत्र में 2020 में भारत ने 612.3 मिलियन यूएस डॉलर का निर्यात और 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का आयात किया। मध्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से भारत द्वारा कच्चे पेट्रोलियम तेल और चांदी के आयात में गिरावट की वजह से कुल व्यापार 2019 के 2.2 बिलियन यूएस डॉलर से घटकर 2020 में 1.9 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। भारत के पास शुरू में 2011 के दौरान इस क्षेत्र में 218 मिलियन यूएस डॉलर का व्यापार अधिशेष था। 2014 में यह 380.7 मिलियन यूएस डॉलर के व्यापार घाटे में बदल गया, जो 2020 में बढ़कर 692.8 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया और 2019 के दौरान अब तक के सबसे उच्च स्तर के साथ 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। इस क्षेत्र में भारत का निर्यात 2011 से 2020 की अवधि के दौरान 4% की सीएजीआर से बढ़ा, जबकि इसी अवधि के दौरान आयात 20.9% की सीएजीआर के साथ बढ़ा।

2020 के दौरान, उज़्बेकिस्तान प्रमुख आयातक रहा। 2020 में मध्य एशिया में भारत के कुल निर्यात का लगभग 42.6% हिस्सा सीएआर देशों में था। सीएआर को भारत के निर्यात में उज़्बेकिस्तान का हिस्सा 21.2% रहा और 2011 में एक बार बढ़ा भी था। वहीं, कज़ाकिस्तान का हिस्सा 57% था, जिसमें 2011 में गिरावट आई। 2020 के दौरान भारत से इस क्षेत्र के प्रमुख आयातकों में कज़ाकिस्तान 36.9%, ताजिकिस्तान (7.3%), तुर्कमेनिस्तान (7.2%) और किर्गिज़स्तान (6%) शामिल रहे।

जहां आयात के संबंध में, सीएआर देशों में से कज़ाकिस्तान, भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। 2020 में इस क्षेत्र से भारत के कुल आयात का 98.3% से अधिक कज़ाकिस्तान से ही आया। इस क्षेत्र से भारत को निर्यातों में कज़ाकिस्तान का हिस्सा 62.5% से बढ़ गया है, जबकि उज़्बेकिस्तान का हिस्सा 2011 में 26.6% से कम हो गया है। इस क्षेत्र से भारत के कुल आयातों में उज़्बेकिस्तान का हिस्सा 1.2% ही रहा। इसके बाद 2020 में किर्गिज़स्तान (0.4%) और तुर्कमेनिस्तान (0.1%) का स्थान रहा।

मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत का व्यापार, 2011 से 2020

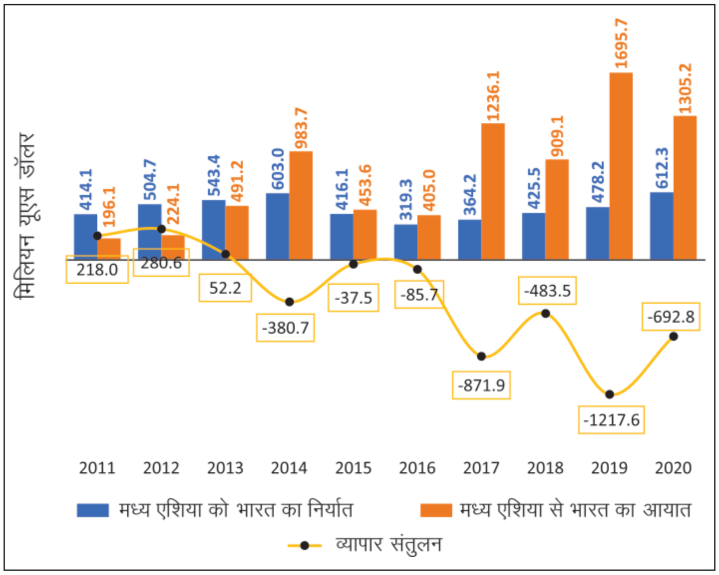

स्रोत : आईटीसी ट्रेडमार्क और इंडिया एक्ज़िम बैंक अनुसंधान

फार्मासूटिकल्स भारत द्वारा इस क्षेत्र को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु है। 2020 के दौरान भारत के कुल निर्यातों में इसका 51.3% हिस्सा रहा। अन्य प्रमुख निर्यात वस्तुओं में मशीनरी और यांत्रिक उपकरण (भारत के कुल निर्यातों का 11.6% हिस्सा), इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण (9.8%), कॉफी, चाय और मसाले (5.4%), लोहे और स्टील का सामान (2.5%), और परिधान और कपड़ों का बिना बुना हुआ या क्रोशिया किया गया सामान (2.1%) शामिल रहा।

आयातों के संबंध में, 2020 के दौरान खनिज ईंधन, तेल और आसवन के उत्पादों का इस क्षेत्र से भारत के कुल आयात में 96% से अधिक का योगदान रहा। आयात की गई अन्य प्रमुख वस्तुओं में मोती, कीमती या अर्ध कीमती रत्न और धातु (कुल आयात का 1.4%), अकार्बनिक रसायन (0.5%) और जहाज, नाव, और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर (0.4%) शामिल रही।

भारत-सीएआर निवेशों में रुझान

सीएआर को भारत के बढ़ते निर्यात के साथ, द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंध उल्लेखनीय रूप से बढ़े हैं। इससे इस क्षेत्र के देशों में भारत का विदेशी निवेश हुआ। हालांकि, भारत और सीएआर के बीच द्विपक्षीय निवेश का प्रवाह पिछले कुछ वर्षों में मामूली रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 1996 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान मध्य एशिया में संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों

में संचयी भारतीय निवेश 323.3 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। सीएआर देशों में से कज़ाकिस्तान, भारत के विदेशी निवेश के लिए एक महत्त्वपूर्ण गंतव्य के रूप में उभरा है। इसी अवधि के दौरान इस देश में कुल 263.7 मिलियन यूएस डॉलर के निवेश को मंजूरी दी गई। इस क्षेत्र में भारत के किए गए कुल निवेश में इस देश का 81.6% हिस्सा रहा, जिसमें अधिकांश निवेश कृषि और खनन क्षेत्र में किया गया। इस क्षेत्र के अन्य देशों में, उज़्बेकिस्तान ने भी भारत के कुल निवेश के 10% के हिस्से के लिए बड़े पैमाने पर भारतीय निवेश को आकर्षित किया और यह मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में रहा। वहीं, किर्गिज़स्तान में निवेश इस क्षेत्र में कुल निवेशों का 4.7% रहा। अप्रैल 1996 से मार्च 2021 के दौरान मध्य एशिया में भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की 0.1% की मामूली हिस्सेदारी रही। कोयला, तेल और गैस को सबसे अधिक निवेश मिला। इसके बाद अक्षय ऊर्जा, कपड़ों, दवाइयों, वित्तीय सेवाओं, होटल और पर्यटन का स्थान रहा।

मध्य एशियाई गणराज्यों में भारत की निर्यात संभावनाएं

भारत और सीएआर के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की रणनीति में सीएआर को भारत से निर्यात की जा सकने वाली संभावित वस्तुओं को चिह्नित करना होगा। इससे भारत की वैश्विक निर्यात क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और यह सीएआर में मौजूदा मांग के अनुरूप होगा, जैसा कि सीएआर की प्रमुख आयातित वस्तुओं में बढ़ते रुझान में देखा जा सकता है। साथ ही, इस तरह की रणनीति इन देशों के प्रमुख आयात भागीदार के रूप में भारत की रैंकिंग बढ़ाने का काम भी करेगी। भारत से इस क्षेत्र को निर्यात की जा सकने वाली कुछ संभावित वस्तुओं की जानकारी नीचे दी गई है।

भारत से कज़ाकिस्तान को निर्यात की जाने वाली संभावित वस्तुओं में अन्य के साथ-साथ मशीनरी; विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण; रेलवे या ट्रामवे के अलावा अन्य वाहन; लोहे या स्टील का सामान; फार्मासूटिकल्स; पेट्रोलियम उत्पाद; प्लास्टिक और प्लास्टिक का सामान; ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक, चिकित्सा या शल्य चिकित्सा उपकरण; लोहा और स्टील, विमान, अंतरिक्ष यान और उसके पुर्जे शामिल होंगी।

भारत से उज़्बेकिस्तान को निर्यात की जाने वाली संभावित वस्तुओं में मुख्य रूप से मशीनरी; परिवहन वाहन; लोहा और स्टील; विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण; पेट्रोलियम उत्पाद; प्लास्टिक और प्लास्टिक का सामान; ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक, सिनेमैटोग्राफिक और चिकित्सा उपकरण; अनाज; और लोहे या स्टील की वस्तुएं शामिल होंगी।

तुर्कमेनिस्तान के मामले में, निर्यात की जाने वाली संभावित वस्तुओं में मशीनरी; लोहे या स्टील का सामान; विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण; परिवहन वाहन; लोहा और स्टील; फर्नीचर, बिस्तर, गद्दे और गद्दे का सामान; विविध रासायनिक उत्पाद; और प्लास्टिक तथा प्लास्टिक का सामान शामिल होगा।

भारत से किर्गिज़स्तान को निर्यात की जाने वाली संभावित वस्तुओं में मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद; मशीनरी; विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण; परिवहन वाहन; लोहे या स्टील की वस्तुएं; लोहा और स्टील; प्लास्टिक और प्लास्टिक का सामान; और जूते-चप्पल शामिल होंगे।

ताजिकिस्तान के लिए, भारत से ताजिकिस्तान को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद; अनाज; लोहा और स्टील; मशीनरी; परिवहन वाहन; विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण; लकड़ी और लकड़ी का सामान; पशु या वनस्पति वसा और तेल; अकार्बनिक रसायन; और प्लास्टिक और प्लास्टिक के सामान शामिल होंगे।

मध्य एशियाई गणराज्यों में निवेश की संभावना

मध्य एशियाई क्षेत्र को एशिया और यूरोप और इसके गतिशील पड़ोसियों - रूस, भारत और चीन के बीच में स्थित होने से तुलनात्मक लाभ मिलता है। इसलिए, यह तेजी से निवेश अनुकूल क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। नीचे ऐसे कुछ संभावित क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं, जिनमें भारतीय निवेशक निवेश करने पर विचार कर सकते हैं:

कज़ाकिस्तान: तेल रिफाइनिं2ग और तेल तथा गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, खनन और मेटालर्जिकल क्षेत्र, रसायन उद्योग, फार्मासूटिकल्स, स्वास्थ्यसेवा, अक्षय ऊर्जा और कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण।

उज़्बेकिस्तान: तेल तथा गैस उद्योग, खनिज संसाधन, रसायन उद्योग, सौर ऊर्जा तथा फल एवं वनस्पति उत्पादों का प्रसंस्करण।

ताजिकिस्तान: ऊर्जा और जल विद्युत, कृषि विकास और कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, पर्यटन और सेवा उद्योग।

किर्गिज़स्तान: जलविद्युत, खनन, खाद्य प्रसंस्करण और सूचना प्रौद्योगिकी।

तुर्कमेनिस्तान: तेल और गैस उत्पादन और रिफाइनिंग तथा रासायनिक उत्पाद।

भारत और मध्य एशिया उन्नत व्यापार और बेहतर संपर्क की आवश्यकता

वर्ष 2021, मध्य एशियाई देशों के लिए यूएसएसआर के विघटन के बाद स्वतंत्रता के 30 वर्षों और भारत के आर्थिक सुधारों का प्रतीक है। यूरेशियन भूभाग के केंद्र में स्थित होने के बावजूद अपनी भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से बंदरगाहविहीन ये पांच राष्ट्र तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।

इस क्षेत्र के साथ सीमित संपर्क और न्यून आर्थिक संबंधों की वजह से मध्य एशिया के साथ भारत का व्यापार सिर्फ 2 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो 2020 में भारत के वैश्विक व्यापार का 0.4% था। इससे पता चलता है कि कनेक्टिविटी और व्यापार से संबंधित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने पर भारत और सीएआर के बीच व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में भारत का निवेश भी कम है और इसे पारंपरिक तेल और गैस क्षेत्रों के अलावा कृषि व्यवसाय, फार्मासूटिकल्स और स्वास्थ्य सेवा, आईटी और रासायनिक क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में सहयोग से बढ़ाया जा सकता है। रेल, सड़क, और ऊर्जा क्षेत्र सहित सीएआर में बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाओं में निवेश, भारतीय निवेशकों के लिए कुछ व्यावहारिक विकल्प हैं। परियोजना निर्यात में भारत की ताकत इन क्षेत्रीय बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में निवेश का मार्ग प्रशस्त करेगी। ■

मुक्त व्यापार समझौतों में भारत की भागीदारी

कोविड-19 के प्रकोप ने भारत सहित दुनिया भर में व्यवधान पैदा किया, जिसमें बाहरी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। भारत का लक्ष्य 2024-25 तक 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद को हासिल करना है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात की प्रमुख भूमिका होगी, क्योंकि इस लक्ष्य में इनके 20% (1 ट्रिलियन यूएस डॉलर) के योगदान की उम्मीद है।

साल 2019 में वस्तुओं और सेवाओं का भारत का संयुक्त निर्यात 538 बिलियन यूएस डॉलर दर्ज किया गया था, जो कि 3% से कम की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा। इसके बाद कोविड-19 के प्रकोप के बीच 2020 में लगभग (-) 11% की साल-दर-साल गिरावट आई। ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि वित्त वर्ष 2012 में कुल निर्यात 670 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें व्यापारिक निर्यात 420 बिलियन यूएस डॉलर को पार कर गया। जबकि सेवाओं का निर्यात 250 बिलियन यूएस डॉलर का रहा।

व्यापार समझौतों का औचित्य

पिछले दो दशकों में, व्यापार विश्व अर्थव्यवस्था में तेजी से विस्तार का एक प्रमुख कारक रहा है। व्यापार करारों के औचित्य के संबंध में कई वजहें हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्निखित शामिल हैं- व्यापार और निवेश के लिए कुछ बाधाओं को कम करना या समाप्त करना, भागीदार देशों के बीच मजबूत व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को सुगम बनाना, आर्थिक सुधार करने की क्षमता, अपनी राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए व्यापार की वरीयता शर्तें आदि। साथ ही, मुक्त व्यापार करारों से वरीयतन रोजगार, नए बाजार और निवेशों में वृद्धि होती है।

इसके अलावा, उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आरटीए) की संचयी संख्या 1990 में 22 थी, जो 2020 में बढ़कर 305 हो गई। भले ही व्यापारिक भागीदारों के बीच गैर-भेदभाव विश्व व्यापार संगठन के मूल सिद्धांतों में से एक है, तथापि इन समझौतों में एक छूट दी गई है, जो निश्चित नियमों के अधीन डब्ल्यूटीओ के तहत अधिकृत हैं।

भारत के प्रमुख व्यापार समझौतों का आकलन

आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौता (एआईएफटीए)

भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के बीच मौजूदा मुक्त व्यापार समझौता तीन पहलुओं में विभाजित है वस्तु में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, और निवेश। समझौते में, आसियान से भारत के आयात का लगभग 70% वरीयता आयात है। भारत से आसियान के आयात के संबंध में, वरीयता आयात 48% को कवर करते हैं।

भारत, एआईएफटीए एकत्रीकरण के साथ वस्तुओं का निवल आयातक बना हुआ है। व्यापार घाटे में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह 2010 में 6.7 बिलियन यूएस डॉलर का था, जो 2021 में बढ़कर 24.2 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। मुख्य रूप से कोयले, कच्चे पाम तेल और पेट्रोलियम तेल के उच्च आयात की वजह से व्यापार संतुलन कम हो गया था।

आसियान समूह को भारत के समग्र व्यापारिक निर्यात के लिए निर्धारित करने वाला व्यापार तीव्रता सूचकांक (टीआईआई) एक से अधिक है। यह दर्शाता है कि व्यापार प्रवाह अपेक्षा से अधिक है।

भारत-दक्षिण कोरिया सीईपीए

भारत-कोरिया सीईपीए जनवरी 2010 में लागू हुआ था। समझौते के अनुसार, दक्षिण कोरिया ने 93% भारतीय आयात पर शुल्क समाप्त कर दिया और भारत ने कोरियाई आयात के 75% हिस्से के लिए ऐसा किया। भारत 2010 और 2021 के दौरान दक्षिण कोरिया से माल का शुद्ध आयातक बना हुआ है। इसमें 2021 में व्यापार घाटा 10 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। जबकि यह 2010 में दर्ज 6.3 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक रहा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बड़े पैमाने पर घाटा विद्युत मशीनरी, लोहा और स्टील, मशीनरी और प्लास्टिक के उच्च आयात की वजह से हुआ।

यह देखा गया है कि समग्र निर्यात के लिए दक्षिण कोरिया को भारत का टीआईआई एक से कम रहा और विशेष रूप से लोहा और स्टील, विद्युत मशीनरी, कार्बनिक रसायन और खनिज ईंधन के लिए कम रहा।

भारत-जापान सीईपीए

भारत-जापान सीईपीए अगस्त 2011 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य भारत में जापानी निर्यात के 90% और भारत से आयात के 97% उत्पादों पर टैरिफ को खत्म करना था। भारत 2010 और 2021 के दौरान जापान से माल का शुद्ध आयातक रहा है। इसमें व्यापार घाटा 2021 में 8.3 बिलियन यूएस डॉलर रहा, जो 2010 में दर्ज 3.5 बिलियन यूएस डॉलर से काफी अधिक है। भारत-जापान वरीयता व्यापार में, वरीयता मार्जिन भारत के आयात पक्ष में अधिकांश वस्तुओं के मामले में अधिक है। वहीं जापान की तरफ वरीयता मार्जिन अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि भारत पहले से ही जापान में कम या शून्य एमएफएन टैरिफ इस्तेमाल कर रहा है। जापान को कुल वस्तु निर्यात के लिए टीआईआई भारत के लिए एक से कम है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत 2021 में ऑस्ट्रेलिया के लिए माल का शुद्ध आयातक रहा। इसका व्यापार घाटा 8.2 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। जबकि 2010 में 10.4 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार घाटा था।

भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए एक दशक से अधिक समय में किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है। समझौते में विविध क्षेत्रों जैसे वस्तु व्यापार, उत्पाद के मूल स्थान से संबंधित नियम, सेवाओं में व्यापार, टीबीटी,

एसपीएस उपाय, विवाद निपटान आदि शामिल हैं। फार्मासूटिकल उत्पादों के लिए नियामक प्रक्रियाओं को आसान बनाते हुए भारत को अपने उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच का लाभ मिलने की भी उम्मीद है। साथ ही, ऑस्ट्रेलिया में भारत 12 बिलियन यूएस डॉलर का बाजार बना रहा है।

भारत और विकसित क्षेत्रों के बीच संभावित व्यापार समझौते

भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते (बीटीआईए)

जून 2007 में, वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार को उदार बनाने के लिए, भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश (बीटीआईए) पर वार्ता शुरू की गई थी। भारत यूरोपीय संघ के 27 देशों को माल का निवल निर्यातक है। इसका व्यापार अधिशेष लगभग 5 बिलियन यूएस डॉलर का है। भारत से यूरोपीय संघ को निर्यातों में मुख्य रूप से खनिज ईंधन, जैविक रसायन, मशीनरी, कीमती धातु और परिधान और कपड़े शामिल हैं। इस समझौते की वार्ताओं में सेवाओं और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर चर्चा की जा सकती है।

भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता

ब्रेक्ज़िट के बाद, भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते की संभावनाएं एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई हैं, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के साथ-साथ निवेश भी शामिल हैं। पिछले दस वर्षों के दौरान, दोनों देशों के बीच व्यापार पैटर्न उच्च स्तर की पूरकता दिखाते हैं। भारत यूके के लिए वस्तुओं का निवल निर्यातक रहा है। इसका व्यापार अधिशेष 2021 में 3.6 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया है। एयरोस्पेस और पुर्जे तथा स्कॉच और व्हिस्की वार्ता के दौरान चर्चा के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल हैं।

भारत के व्यापार समझौते : आगे की राह

मौजूदा एफटीए में असमान आदान-प्रदान को संबोधित करना

ज्यादातर मामलों में, जब भारत आयात के पक्ष में होता है, तो वरीयता टैरिफ एमएफएन टैरिफ की तुलना में काफी कम होते हैं। जबकि भारत के भागीदार देश के लिए, वरीयता टैरिफ आयात करते समय एमएफएन टैरिफ के करीब होते हैं। परिणामतः, यदि भागीदार देश अपने आयात को भारत से करने का निर्णय लेते हैं तो हो सकता है कि उन देशों को अधिक लाभ न मिले। ऐसा इसलिए, क्योंकि वरीयता का मार्जिन अपेक्षाकृत कम है। ये भारत के व्यापार समझौतों में मौजूद लाभों का असमान वितरण है।

असमान विनिमय की समस्या का समाधान करने के लिए शून्य-बजट के माध्यम से मौजूदा और संभावित एफटीए का पुनर्मूल्यांकन करना महत्त्वपूर्ण है। एफटीए की पुनः वार्ताओं में मौजूदा उल्टे शुल्क ढांचे की समस्या का समाधान भी होना चाहिए। साथ ही, ऑफसेट अनुच्छेद का समावेश भी करना चाहिए, जैसा कि अक्सर सौदों या समझौतों के माध्यम से रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए किया जाता है। इनका विस्तार व्यापक व्यापार समझौतों, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रौद्योगिकी गहन क्षेत्रों के लिए करना चाहिए।

एफटीए में व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते को शामिल करना

आधुनिक दुनिया में, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं (टीबीटी) टैरिफ की तुलना में भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापार को प्रतिबंधित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। विश्व व्यापार संगठन का टीबीटी समझौता उन तकनीकी विनियमों, मानकों, और परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रियाओं को चिह्नित करने के लिए रूपरेखा तैयार करता है, जो अन्य देशों में व्यापार के लिए अनावश्यक बाधाएं पैदा नहीं करते हैं।

सुझाया गया है कि भारत के व्यापार समझौते, विशेष रूप से विकसित देशों के साथ, व्यापक और छोटे हों और विश्व व्यापार संगठन के टीबीटी समझौते की नींव तथा प्रावधानों पर आधारित हो, ताकि घरेलू रूप से निर्मित वस्तुओं को व्यापक बाजार पहुंच दी जा सके।

आपातकालीन कार्य योजना का प्रावधान

भारत द्वारा किए जाने वाले व्यापार समझौतों में एक संक्रमणकालीन टैरिफ-आधारित आपातकालीन कार्रवाई तंत्र प्रदान करना चाहिए, जो एक अस्थायी द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय है। इसका इस्तेमाल घरेलू उद्योग और निर्यातकों को उन घटनाओं से बचाने के लिए किया जाता है, जो आयात में अभूतपूर्व उछाल या निर्यात में गिरावट के रूप में अप्रत्याशित क्षति की वजह बन सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था व्यापक होनी चाहिए और इसे लागू करने के लिए योग्यता की शर्तें और उस अवधि को निर्दिष्ट करना चाहिए जिसमें कार्रवाई की जा सके।

व्यापार समझौतों की वार्ता में अन्य विकासशील देशों के एफटीए भागीदारों के साथ एक "ग्रैजुएशन क्लॉज़" का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है, जिसमें चुनिंदा समझौतों की शर्तों की आवधिक समीक्षा के लिए एक "सनसेट क्लॉज़" हो। अगर एफटीए में आयात में अचानक वृद्धि होती है तो एक "ट्रिगर मैकेनिज़्म" भी हो।

सेवाओं में व्यापार प्रतिबंधों को कम करना

भारत का सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक (एसटीआरआई) स्कोर सभी क्षेत्रों में विश्व औसत से अधिक है और कुल 22 सेवाओं में से 3 में सबसे अधिक है। क्षेत्रों में, रेल माल परिवहन का एसटीआरआई मूल्य सबसे अधिक (1) है, जो अधिकतम एसटीआरआई मूल्य है। उच्च एसटीआरआई मूल्यों वाले दो अन्य क्षेत्र कानूनी सेवाएं (0.886) और लेखा सेवाएं (0.827) हैं।

इस क्षेत्र में कमियों को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए सुझाया गया है कि वर्तमान और संभावित व्यापार समझौतों में पर्याप्त उप-क्षेत्रीय कवरेज के साथ सेवाओं में व्यापार को और अधिक उदार बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

सीईपीए में गतिविधियां बढ़ाना

भारत को वरीयता विकास संभावनाओं के लिए सीईसीए और सीईपीए जैसे व्यापक आर्थिक समझौते करने पर ध्यान देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि सीईपीए अनिवार्य रूप से एफटीए पैकेज है, जिसमें वस्तुओं या सेवाओं, निवेश, आपसी मान्यता, ई-कॉमर्स, बौद्धिक संपदा और अन्य सामग्री पर समझौते का एक एकीकृत पैकेज भी शामिल है। यह सरकार की महत्त्वाकांक्षी "असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड" योजना के लिए भी अहम हो सकता है, जिसके तहत मौजूदा "मेक इन इंडिया" के साथ "असेंबल इन इंडिया" का विलय किया जा रहा है। ■

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के व्यापार और निवेश संबंध

संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत का संबंध "विस्तारित पड़ोस नीति" के तहत सम्मिलित खाड़ी की एक मुखर नई नीति के केंद्र में है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना इस क्षेत्र में भारत की विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने अपनी 2.6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संसाधनों के प्रमुख उपभोक्ता और बड़ी प्रवासी आबादी के साथ संयुक्त अरब अमीरात के लिए बढ़ी हुई प्रमुखता हासिल कर ली है। इससे भारत संयुक्त अरब अमीरात के लिए एक रणनीतिक भागीदार बन गया है। भारत-यूएई द्विपक्षीय संबंधों में दो प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं: आर्थिक सहजीवन और भारत का प्रवासी समुदाय। भारत-यूएई संबंधों के इन दोनों परस्पर जुड़े स्तंभों ने भारत-यूएई संबंधों को और विस्तारित करने का मार्ग दिखाया है। भारत-यूएई के बढ़ते आर्थिक संबंध, दोनों देशों के बीच तेजी से विविधीकृत होते और गहराते द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ कर रहे हैं।

वस्तु व्यापार

हाल के दिनों में, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत का कुल व्यापार 2010 के 58.3 बिलियन यूएस डॉलर से घटकर 2020 में 41.9 बिलियन यूएस डॉलर का रह गया। वहीं, निर्यात 2010 में 27.4 बिलियन यूएस डॉलर का था, जो 2020 में घटकर 18.0 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। इसके अलावा, आयात में भी गिरावट आई है, जो 2010 के 30.9 बिलियन यूएस डॉलर से घटकर 2020 में 23.9 बिलियन यूएस डॉलर का रह गया। हालांकि, 2020 में, महामारी के कारण आए व्यवधान और तेल की कीमतों के स्तर में गिरावट की वजह से पूरे व्यापार में उल्लेखनीय गिरावट आई है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के व्यापार संतुलन में घाटे और अधिशेष की चक्रीय उतार-चढ़ाव देखा गया है। वर्ष 2010 में, कुल घाटा 3.5 बिलियन यूएस डॉलर का था, जो 2020 में बढ़कर 5.9 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया।

निर्यात: वर्ष 2020 में यूएई को निर्यात किए गए भारत के प्रमुख उत्पादों में खनिज ईंधन, तेल और उसके उत्पाद (2020 में कुल निर्यात का 19%) शामिल रहे। इसके बाद मोती, कीमती रत्न और धातु (18.5%), विद्युत मशीनरी और उपकरण (9%), परिधान और कपड़ों के सामान, साज-सामान (5.0%), लोहा और स्टील (4.5%), मशीनरी और यांत्रिक उपकरण (4.3%) और अन्य उत्पाद शामिल रहे।

आयात: आयात के संबंध में, 2020 में संयुक्त अरब अमीरात से भारत में आयातित प्रमुख उत्पादों में खनिज ईंधन, तेल और उसके उत्पाद (कुल आयात का 49.8%) शामिल रहे। इसके बाद मोती, कीमती रत्न और धातु (28.5%), प्लास्टिक और प्लास्टिक का सामान (3.1%), जहाज, नाव और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर (3%) तथा नमक और सल्फर (2.2%) एवं अन्य उत्पाद शामिल रहे।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंध हाल के वर्षों में कुछ और मजबूत हुए हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों ने एक-दूसरे की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय निवेश किया है और इस प्रकार एक-दूसरे के विकास एजेंडा में सहयोग दिया है।

भारत में संयुक्त अरब अमीरात का निवेश: अप्रैल 2000 से सितंबर 2021 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात, भारत में 9वां सबसे बड़ा निवेशक रहा। उसने भारत के कुल एफडीआई प्रवाह में 2.1% का योगदान दिया। फायनैंशल टाइम्स के एफडीआई मार्केट्स के अनुसार, 2010-2020 के दौरान, संयुक्त अरब अमीरात ने 121 कंपनियों के जरिए 344 परियोजनाओं में 18.1 बिलियन यूएस डॉलर का संचयी निवेश किया। इससे रोजगार के 91,521 अवसरों का सृजन हुआ। यूएई सॉवरेन वेल्थ फंड ने वित्तीय वर्ष 2020-21[1] के दौरान, भारत में 4.12 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक का निवेश किया।

पूंजी निवेश के संदर्भ में, भारत में संयुक्त अरब अमीरात का अधिकांश निवेश रियल एस्टेट क्षेत्र (कुल निवेश का 29.6%) में है। इसके बाद वित्तीय सेवाएं (23%), खाद्य और पेय पदार्थ (16.7%), परिवहन और भंडारण (7.9%), उपभोक्ता उत्पाद (6%), स्वास्थ्य सेवा (5.8%) और धातु (2.8%) आदि का स्थान रहा।

संयुक्त अरब अमीरात में भारत का निवेश: अप्रैल 1996 से मार्च 2021 के दौरान, संयुक्त अरब अमीरात के लिए भारत छठा सबसे बड़ा निवेशक रहा। इस अवधि में कुल 5.2% का निवेश भारत से रहा। फायनैंशल टाइम्स के एफडीआई मार्केट्स के अनुसार, 2010-2020 के दौरान भारत से संयुक्त अरब अमीरात में 270 भारतीय कंपनियों के जरिए 332 परियोजनाओं में 15.9 बिलियन यूएस डॉलर का संचयी निवेश किया। इससे रोजगार के 37,398 अवसरों का सृजन हुआ।

पूंजी निवेश के संदर्भ में, संयुक्त अरब अमीरात में भारत का अधिकांश निवेश रियल एस्टेट क्षेत्र (कुल निवेश का 32.8%) में है। इसके बाद कोयला, तेल, और गैस (14%), रसायन (11.5%), उपभोक्ता उत्पाद (6.5%), होटल और पर्यटन (4.7%), परिवहन और भंडारण (3.7%), और धातु (3%) आदि का स्थान रहा।

भारत के निर्यातों को संयुक्त अरब अमीरात के अनुरूप बनाना

दोनों देशों के बीच व्यापार के तुलनात्मक लाभ विश्लेषण के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात को भारत के निर्यातों को स्पर्धात्मकता के आधार पर 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। भारत की निर्यात स्पर्धात्मकता को संयुक्त अरब अमीरात में मांग के अनुसार मैप किया गया है। ये चार समूह निम्नलिखित अनुसार हैं:

उत्पाद चैंपियन: एचएस 6 स्तर पर 1067 वस्तुओं में से, 506 वस्तुएं उत्पाद चैंपियन (पीसी) की श्रेणी में आती हैं। वर्ष 2019 में भारत से यूएई को इन वस्तुओं

[1] भारत का दूतावास, अबु धाबी, यूएई

का संयुक्त निर्यात 21.1 बिलियन यूएस डॉलर का रहा था, जो 2019 में यूएई को भारत के लगभग 72% निर्यात का प्रतिनिधित्व करता है। निर्यात किए गए प्रमुख उत्पादों में आभूषण और उसका सामान, पेट्रोलियम या बिटुमिनस खनिजों के हल्के तेल और उन्हें बनाने का सामान, मीडियम ऑयल और पेट्रोलियम या बिटुमिनस खनिजों को बनाने का सामान और हल्की नौकाएं, फ्लोटिंग क्रेन और अन्य वेसल आदि शामिल रहे।

गिरावट वाले क्षेत्रों में "विनर": गिरावट वाले क्षेत्रों की श्रेणी में "विनर" उत्पादों की कुल संख्या 146 है, जिसमें 2019 में भारत का निर्यात 2.9 बिलियन यूएस डॉलर का रहा और भारत के निर्यातों में यूएई का 9.8% हिस्सा रहा। ये वे उत्पाद हैं, जिनमें भारत ने संयुक्त अरब अमीरात की आयात सूची में उल्लेखनीय जगह बनाई है। लेकिन पिछले दशक में इन उत्पादों के लिए संयुक्त अरब अमीरात की आयात मांग गिरी है। प्रमुख उत्पादों में अन्य के साथ-साथ हीरे (काम किया हुआ, लेकिन माउंटेड नहीं), थोड़ा पॉलिश किया या पूरा पॉलिश किया चावल, क्रूज जहाज, भ्रमण नौकाएं और इसी तरह के वेसल, लौह-मैंगनीज और मानव निर्मित फाइबर से बनी पुरुषों की शर्ट आदि जैसे उत्पाद शामिल हैं।

अंडरअचीवर: इसके बाद इस श्रेणी में 370 वस्तुएं शामिल रहीं, जिनका भारत से संयुक्त अरब अमीरात को कुल 4.6 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात रहा। ये उत्पाद संयुक्त अरब अमीरात को भारत के कुल निर्यातों में 15.6 फीसदी की हिस्सेदारी रखते हैं। ये ऐसे उत्पाद हैं जिनमें संयुक्त अरब अमीरात के बाजार में मांग बढ़ रही है, लेकिन भारत के पास इन वस्तुओं के निर्यात में आवश्यक स्पर्धात्मकता नहीं है। इस श्रेणी के प्रमुख उत्पादों में अन्य के साथ-साथ सेलुलर नेटवर्क के लिए टेलीफोन, बिना काम किए गए गैर-औद्योगिक हीरे, एल्यूमीनियम ऑक्साइड, चिकित्सकीय या रोगनिरोधी उद्देश्यों के लिए मिश्रित या गैर-मिश्रित उत्पादों से युक्त दवाएं और पाइप, बॉयलर शेल, टैंक, टंकी आदि जैसे उत्पाद शामिल हैं।

गिरावट वाले क्षेत्रों में "लैगर": गिरावट वाले क्षेत्रों की श्रेणी के अंतर्गत निर्यातों की उच्च श्रेणी अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ उन उद्योगों के लिए विविधीकरण की आवश्यकता को उजागर करती है, जिनमें भविष्य में निर्यात की अधिक संभावना है।

इसके अलावा, इस विश्लेषण में इन उत्पादों की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए उत्पाद चैंपियन की श्रेणी में मौजूदा उत्पादों को बढ़ाने की संस्तुति की गई है, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात के बाजार में पहले से ही अच्छी वृद्धि दिख रही है। जबकि भारत के निर्यात में भी उनका तुलनात्मक लाभ है।

भारत-संयुक्त अरब अमीरात सीईपीए

भारत और यूएई ने 18 फरवरी, 2022 को एक व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए। सीईपीए, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) क्षेत्र में भारत का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता भी है।

इस सीईपीए से गहन श्रम क्षेत्रों, रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, जूते-चप्पल, खेल वस्तुएं, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि और लकड़ी के उत्पादों, इंजीनियरिंग उत्पादों, दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से निर्यातों को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय फार्मासूटिकल उत्पादों की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए इस करार में इस बारे में अलग से अनुबंध भी शामिल किया गया है। सेवा व्यापार के क्षेत्र में, इस करार से भारतीय सेवा प्रदाताओं को 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों जैसे व्यापार सेवाओं, संचार सेवाओं, निर्माण और उससे संबंधित इंजीनियरिंग सेवाओं, शैक्षिक सेवाओं, वित्तीय सेवाओं और पर्यटन और यात्रा संबंधी सेवाओं के बाजार तक पहुंच को आसान बना दिया है।

सीईपीए के प्रभावी होने के बाद, संयुक्त अरब अमीरात को होने वाले भारतीय निर्यात के 90% हिस्से के लिए टैरिफ शून्य हो जाएगा। हालांकि इसमें लगभग 80% टैरिफ लाइनें शामिल हैं। मगर सूची में अगले पांच वर्षों में लगभग 97% टैरिफ लाइनें शामिल होंगी। विशेष रूप से, भारत से संयुक्त अरब अमीरात को आभूषण निर्यात पर आयात शुल्क 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, रसायन और पेट्रोकेमिकल, रत्न, सीमेंट, सरैमिक, मशीनरी जैसे उत्पादों के लिए अतिरिक्त 9% व्यापार मूल्य भी 5-10 वर्षों में शुल्क मुक्त होगा।

भारत को यूएई के निर्यात के लिए, लगभग 65% टैरिफ लाइनों पर आयात शुल्क पर तत्काल राहत मिलेगी। इससे 10 वर्षों में टैरिफ लाइनों के 90% तक बढ़ने की उम्मीद है। भारत को पहले वर्ष में, लागू शुल्क से 1% कम शुल्क पर संयुक्त अरब अमीरात से 120 टन सोना आयात करने की अनुमति है। पांच वर्ष में यह मात्रा बढ़कर 200 टन हो जाएगी।

आगे की राह

दोनों देश अपने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सावधानीपूर्वक काम कर रहे हैं। भारत-यूएई सीईपीए पर हस्ताक्षर से इस आर्थिक साझेदारी और साझा दृष्टिकोण को मजबूती मिली है। साथ ही, इससे दोनों देशों के बीच सुदृढ़ आर्थिक संबंधों की इबारत लिखने और व्यापार एवं निवेश के लिए नए रास्ते खोलने की तैयारी दिखाई देती है। हालांकि, इस साझेदारी को और बढ़ाने के लिए कतिपय बाधाओं को दूर करना जरूरी है। इसके लिए सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और समाधान इस द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने में मददगार होगा। इस संबंध में निम्नलिखित नीतिगत उपाय काबिले गौर हैं- (i) चिह्नित वस्तुओं के आधार पर व्यापार का विस्तार, जिनमें भारत के लिए निर्यात क्षमता हो; (ii) निर्यातित उत्पादों के शुल्क-मुक्त आयात से बचने के लिए उत्पत्ति के स्थान संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन; (iii) हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में सहयोग; (iv) द्विपक्षीयता से लघुपक्षवाद की ओर बढ़ना, क्योंकि वे कम देशों के साथ समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिक कार्य-उन्मुख हैं; (v) जीआई टैग वाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, क्योंकि ये भारत के लिए खास हैं और इस वजह से भारत एकाधिकार वाली स्थिति में रहता है; (vi) लेन-देन और परिवहन लागत को कम करने के लिए सहायक रसद बुनियादी ढांचे को बढ़ाना; (vii) आत्मनिर्भर भारत के लिए सीईपीए को बढ़ावा देना, ताकि संयुक्त अरब अमीरात का बाजार भारत की जरूरतों के पूरक के रूप में काम कर सके और साथ ही साथ नई क्षमताओं का निर्माण किया जा सके। ■

वित्त और विकास पर निबंध

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) ने 2016 में ब्रिक्स आर्थिक अनुसंधान वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की थी। इस पुरस्कार का उद्देश्य विश्व स्तर पर किसी भी विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से ब्रिक्स के पांचों सदस्य के नागरिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और संबंधित वित्तपोषण में उन्नत शोध को बढ़ावा देना है। यह अध्ययन डॉ. अपूर्व गुप्ता द्वारा लिखित इंडिया एक्ज़िम बैंक ब्रिक्स आर्थिक शोध वार्षिक पुरस्कार (ब्रिक्स पुरस्कार) 2022 के लिए विजेता प्रविष्टि के रूप में चयनित "वित्त और विकास पर निबंध" नामक शोध प्रबंध पर आधारित है। वर्तमान में डॉ. गुप्ता यूएसए के डार्टमाउथ कॉलेज में अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर हैं। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री 2020 में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, यूएसए से हासिल की थी।

यह अध्ययन तीन निबंधों का एक संग्रह है। इसमें अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को अपनाने और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों तथा आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। पहले अध्याय में इस पहलू का अध्ययन किया गया है कि मांग-पक्ष के कारक कैसे मार्कअप को प्रभावित करते हैं और परिवर्तनीय मार्कअप से उत्पादों का आवंटन कैसे गलत हो जाता है और उसे ठीक करने के लिए कौनसी पद्धति अपनाई जा सकती है। इस विश्लेषण के लिए भारतीय फर्मों से कतिपय आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। इस अध्ययन में दो प्रमुख सहसंबंधों के बारे में जानकारी दी गई है। एक तो यह कि फर्म के आकार में सीमांत लागत और मार्कअप बढ़ रहे हैं। और दूसरा यह है कि ये सहसंबंध कैसे दो कारकों से संचालित होते हैं। इन्हें संचालित करने वाले दो कारक हैं- अमीर उपभोक्ताओं का बड़ी फर्मों के लिए वर्गीकरण मिलान और अमीर उपभोक्ताओं की न्यूनतर मांग इलास्टिसिटी। इसके परिणाम का भी विश्लेषण किया गया है कि अलग-अलग आकार की कंपनियां गरीब परिवारों को बाहरी कारकों से लगने वाले डिमांड शॉक के जवाब में मांग-आधारित मार्कअप चैनल को कैसे सहयोग करती हैः बेहतर गुणवत्ता का उत्पादन करती हैं और अमीरों को उनकी बिक्री करती हैं, कम मांग वाले परिवारों से मांग कम होने से बड़ी फर्मों की लागत बढ़ती है और वे उच्चतर मार्कअप चार्ज करती हैं। यह मांग-संचालित मार्कअप प्रसार पुनः आवंटन से कुल उत्पादकता लाभ को कम करता है, क्योंकि कंपनियां उन नीतियों के जवाब में अपने मार्कअप को भी समायोजित करती हैं जिनसे आवंटन दक्षता में सुधार लाया जा सकता है। फर्मों द्वारा अपनी लागतों को कीमतों में परिवर्तित करना, पुनर्आवंटन से होने वाले उत्पादकता लाभ का आकलन करते समय मार्कअप समायोजन को मापने के लिए अपने आप में पर्याप्त आंकड़ा है। मांग-संचालित परिवर्तनीय मार्कअप की वजह से पुनर्आवंटन से लाभ 50% न्यूनतर है।

दूसरे अध्याय में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जैसी वित्तीय प्रौद्योगिकियों में बड़े, लेकिन अस्थायी शॉक दीर्घावधि में कैसे उस प्रोद्योगिकी को अपनाने के कारक बन जाते हैं। कई फिनटेक उत्पाद नेटवर्क आधारित होते हैं और उनका इस्तेमाल समन्वय से ही किया जा सकता है। इस अध्ययन में, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद भारत में फिनटेक भुगतान के सबसे बड़े प्रदाता के डेटा का अध्ययन किया गया है और इस प्रक्रिया के क्वांटिटेटिव महत्त्व के बारे में बताया गया है। अस्थायी नकदी संकुचन के समाधान के लिए, बाहरी कारकों के साथ डायनैमिक प्रौद्योगिकी अपनाने के मॉडल के अनुरूप, फिनटेक प्लैटफॉर्म के आकार और उन्हें अपनाने की दर, दोनों में लगातार वृद्धि हुई। मॉडल के अनुमान बताते हैं कि छह महीने की प्रतिक्रिया का 45%, बाहरी कारकों द्वारा संचालित था। इसलिए, बाहरी कारकों के चलते, अस्थायी उपायों की वजह से इसे अपनाने में लगातार बदलाव हो सकता है। हालांकि, अध्ययन में इस तर्क की एक उल्लेखनीय बाधा भी बताई गई है कि चूंकि बाह्य कारक व्यवस्थागत निर्भरता को जन्म देते हैं, इसलिए अस्थायी उपायों से दीर्घावधि में इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में शुरुआती अंतर भी आ सकते हैं।

तीसरे अध्याय में कृषि में प्रौद्योगिकी को अपनाने और उत्पादकता के संबंध में सूचनाओं के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। अनुभवजन्य रणनीति में कृषि संबंधी सूचनाओं के प्रसार के लिए कॉल सेंटरों की उपलब्धता के साथ-साथ ग्रामीण भारत में मोबाइल फोन नेटवर्क के विस्तार का लाभ उठाने की संस्तुति की गई है। कृषि पद्धतियों की जानकारी के लिए किसानों द्वारा भारत के प्रमुख कॉल सेंटरों में से एक में किए गए 2.5 मिलियन फोन कॉल की सामग्री का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से पता चलता है कि नए मोबाइल टावरों से कवरेज लेने वाले और किसानों तथा उनके कॉल का जवाब देने वाले सलाहकारों के बीच यदि भाषाई बाधा नहीं है तो ऐसे किसान उच्च उत्पादकता वाले बीजों तथा अन्य सामग्री के इस्तेमाल से अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। आकलनों से संकेत मिलता है कि समुचित जानकारी के प्रसार से हमारे नमूने में सबसे अधिक उत्पादक और सबसे कम उत्पादक क्षेत्रों के बीच कृषि उत्पादकता के अंतर को लगभग 25% तक कम किया जा सकता है। ■

इंडिया एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं

इंडिया एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। ये ऋण-व्यवस्थाएं उन देशों के क्रेताओं को भारत से विकासपरक तथा बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं। इंडिया एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इनके अंतर्गत इंडिया एक्ज़िम बैंक माल के शिपमेंट पर भारतीय निर्यातकों को कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के 100% की प्रतिपूर्ति करता है, बशर्ते कि कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के कम से कम 75% के माल एवं सेवाओं का आयात भारत से किया गया हो। ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता के प्रदर्शन में भी मदद मिली है। हाल के वर्षों में ऋण-व्यवस्थाओं ने गति पकड़ी है। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। ऋण-व्यवस्थाओं ने भारत के राजनीतिक, रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने के साथ-साथ लाभार्थी देशों में भारत की राजनीतिक ख्याति को बढ़ाने का काम भी किया है। ऋण-व्यवस्थाएं भारत की बढ़ी आर्थिक मजबूती के साथ-साथ इन ऋण-व्यवस्थाओं के प्राप्तकर्ता देशों में बुनियादी ढांचागत विकास और क्षमता निर्माण में योगदान देने की प्रतिबद्धता को वैश्विक पटल पर लाने में भी मदद करती हैं। ऋण-व्यवस्थाएं प्राप्तकर्ता देशों के ऐसे बाजारों में जरूरी माल और सेवाओं के निर्यात में भी मददगार हैं, जहां भारत की मौजूदगी न के बराबर है। भारतीय निर्यातक इंडिया एक्ज़िम बैंक से अपने माल के लिए पात्र मूल्य हासिल कर सकते हैं और इसके लिए उन पर किसी तरह का रिकोर्स नहीं रहता। बैंक द्वारा शिपिंग दस्तावेजों के निगोशिएशन/ सेवाओं के प्रावधान के एवज में किया जाता है। भारतीय निर्यातक माल के शिपमेंट पर इंडिया एक्ज़िम बैंक के जरिए पूरा भुगतान ले सकते हैं और इसमें उन्हें क्रेता या क्रेता देश से जुड़े किसी तरह के जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता।

ऋण-व्यवस्थाएं संप्रभु सरकारों को या उनकी नामित एजेंसियों को प्रदान की जाती हैं, ताकि उन देशों में क्रेता भारत से माल और सेवाओं का आस्थगित भुगतान शर्तों पर आयात कर सकें। बैंक द्वारा यथा 22 जून, 2022 को अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों के 66 देशों को 31.96 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 310 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण-व्यवस्थाएं विकासशील देशों में भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात के संवर्धन और सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार के सहयोग से, नीचे दी गई जानकारी के अनुसार अप्रैल-जून, 2022 की अवधि के दौरान एक शॉर्ट टर्म एलओसी पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार की ओर से श्रीलंका सरकार को 55 मिलियन यूएस डॉलर की अल्पावधि ऋण-व्यवस्था प्रदान की है। यह ऋण-व्यवस्था यूरिया खाद की खरीद के लिए प्रदान की गई है। इस अल्पावधि ऋण-व्यवस्था करार पर 10 जून, 2022 को कोलंबो में हस्ताक्षर किए गए। इस पर श्री के. एम. महिंदा सिरिवरदाना, सचिव, वित्त, आर्थिक स्थिरीकरण एवं राष्ट्रीय नीति मंत्रालय, श्रीलंका सरकार और श्री निर्मित वेद, महाप्रबंधक, एक्ज़िम बैंक ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर श्रीलंका के माननीय और श्रीलंका में भारत के माननीय उच्चायुक्त श्री गोपाल बागले उपस्थित रहे। 55 मिलियन यूएस डॉलर के इस ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर के साथ ही एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से श्रीलंका सरकार को अब तक 2.73 बिलियन यूएस डॉलर की कुल 11 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। श्रीलंका सरकार को प्रदत्त ये ऋण-व्यवस्थाएं पेट्रोलियम उत्पादों, रेलवे परियोजनाओं, रक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर की आपूर्ति के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:
श्री निर्मित वेद, महाप्रबंधक
इंडिया एक्ज़िम बैंक,
ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 1, 7वीं मंज़िल, एड्जेसेंट रिंग रोड,
किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली 110023,
फोन : +91-11-24607710
ई-मेल: eximloc@eximbankindia.in
वेबसाइट: www.eximbankindia.in

दास्तान-ए-कामयाबी

नेपाल सरकार को प्रदत्त इंडिया एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार समर्थित 250 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने राजमार्गों, हवाई अड्डों, पुलों, और सिंचाई परियोजना जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए नेपाल सरकार को भारत सरकार की ओर से 250 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की है। इस समझौते पर 21 अक्टूबर, 2011 को हस्ताक्षर किए गए थे।

परियोजना का विवरण:

इस संबंध में हुए कॉन्ट्रैक्ट पर मोहन एनर्जी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच हस्ताक्षर किए गए। इसे 8 अगस्त, 2016 को ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया गया।

इस परियोजना के अंतर्गत सोलू कॉरिडोर 132केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के प्लांट डिजाइन, आपूर्ति और स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है।

परियोजना की कुल लागत- 2,90,00,000 यूएस डॉलर

परियोजना 5 अप्रैल, 2022 (परिचालन समापन) को सफलतापूर्वक पूरी हुई।

तिमाही गतिविधियां

"भारत–ऑस्ट्रेलिया: बदलता व्यापार और निवेश परिदृश्य" विषय पर एक्ज़िम बैंक का सेमिनार

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने 08 अप्रैल, 2022 को "भारत-ऑस्ट्रेलियाः बदलता व्यापार और निवेश परिदृश्य" विषयक अपने वेबिनार के दौरान "ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का व्यापार और निवेश संबंधः हालिया रुझान और संभावना" विषयक अपने शोध अध्ययन का विमोचन किया। इस शोध अध्ययन का विमोचन भारत में ऑस्ट्रेलिया के माननीय उच्चायुक्त श्री बैरी ओ"फैरेल एओ द्वारा किया गया। इस दौरान मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत श्री पीटर ट्रसवेल और इंडिया एक्ज़िम बैंक की प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। साथ ही, एक्सपोर्ट फायनेंस ऑस्ट्रेलिया के मुख्य जोखिम अधिकारी और जनरल काउंसिल श्री जॉन हॉपकिन्स; ऑस्ट्रेड, मुंबई की वरिष्ठ व्यापार एवं निवेश आयुक्त डॉ. मोनिका केनेडी; ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिज़नेस काउंसिल के न्यू साउथ वालेस चैप्टर के प्रेसीडेंट श्री इरफान मलिक; और गेटवे हाउस मुंबई के सीनियर फैलो श्री अमित भंडारी भी उपस्थित रहे।

इस शोध अध्ययन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और बढ़ाने के लिए मौजूद अवसरों का उल्लेख किया गया है। इसमें 2020 तक की अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच कुल व्यापार का विश्लेषण किया गया है। शोध अध्ययन में बताया गया है कि 2017 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 18 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया था। इसमें निर्यात और आयात की बात की जाए तो भारत से ऑस्ट्रेलिया को 4 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया गया और ऑस्ट्रेलिया से भारत में 14 बिलियन यूएस डॉलर का आयात किया गया था।

परियोजना निर्यातों के लिए वित्तपोषण का ढांचा मजबूत बनाना हो प्राथमिकता: श्री पीयूष गोयल

"वित्तपोषण के नवोन्मेषी माध्यमों के जरिए परियोजना निर्यातों के लिए वित्तपोषण के ढांचे को मजबूत बनाना और निर्यात ऋण एजेंसियों के लिए विवेकसम्मत मानदंड जैसे विनियमों की समीक्षा करना प्राथमिकता होनी चाहिए।" यह बात माननीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) द्वारा 05 मई, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन के दौरान कही। यह सम्मेलन "भारतीय परियोजना निर्यातकों के लिए वैश्विक अवसर बढ़ाना" विषय पर आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अन्य के साथ-साथ, भारतीय परियोजना निर्यातकों के अलावा,भारत सरकार और भारत में विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधियों, विकास वित्त संस्थाओं, ऋण बीमा एजेंसियों और भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में 150 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।

सम्मेलन के दौरान श्री गोयल ने महामारी की बाधाओं के बावजूद भारतीय परियोजना निर्यातों के उल्लेखनीय स्तर पर बने रहने को रेखांकित किया। श्री गोयल ने उल्लेख किया कि देश वस्तुओं और सेवाओं, प्रत्येक के निर्यातों में 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर के वृहत्तर लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और परियोजना निर्यातों जैसे उभरते क्षेत्र इसके लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने कैमरून सरकार को 164.69 मिलियन यूएस डॉलर का क्रेता ऋण सुविधा प्रदान की

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) ने कैमरून में 173.36 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य की 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन एवं इससे संबन्धित सब-स्टेशनों के निर्माण के लिए कैमरून गणराज्य सरकार के साथ 11 मई, 2022 को एक क्रेता ऋण करार पर हस्ताक्षर किए। इस राशि को राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) योजना के तहत प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना से अन्य के साथ-साथ कैमरून के उत्तरी क्षेत्र में 8 मिलियन से ज्यादा लोगों को बिजली की आपूर्ति होगी, जिससे उनके सामाजिक-आर्थिक जीवन में सुधार होगा। यह परियोजना कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लि. (KPTL) द्वारा निष्पादित की जाएगी।

कोविड–19 से निपटने के लिए भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को सहयोग, इंडिया एक्ज़िम बैंक और जेबिक में 100 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण करार

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) ने कोविड-19 महामारी से संबंधित भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को सहयोग करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनैशनल कॉपरेशन (जेबिक) के साथ वर्चुअल रूप से 100 मिलियन यूएस डॉलर के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए। यह ऋण करार 23 मई, 2022 को टोक्यो, जापान में हुए चतुर्भुज राष्ट्रों के नेताओं के सम्मेलन के दौरान अलग से किया गया। बैंक ने यह ऋण करार तीन और जापानी निजी वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर किया है। ये संस्थाएं हैं- एमयूएफजी बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ क्योटो लिमिटेड और हाचीजुनी बैंक लिमिटेड। इस ऋण सुविधा का उद्देश्य कोविड-19 से मुकाबले के लिए भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को सहयोग करने के साथ-साथ, टीका विनिर्माताओं, फार्मासूटिकल कंपनियों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) विनिर्माताओं, चिकित्सा ऑक्सीजन या अन्य मेडिकल डिवाइस विनिर्माताओं और अस्पतालों तथा संबंधित अन्य गतिविधियों को सहयोग करना है।

माननीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने लॉन्च किया इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा विकसित "नेत्र" (न्यू ई–ट्रैकिंग एंड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन) प्लैटफॉर्म

ऐसे समय में जब देश अमृत महोत्सव से अमृत काल की ओर बढ़ रहा है, श्रीमती सीतारामन ने विकास भागीदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता की तरफ ओर एक और कदम के रूप में "नेत्र" (न्यू ई-ट्रैकिंग एंड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन) नाम का एक प्लैटफॉर्म भी लॉन्च किया। यह डायनैमिक मॉनिटरिंग प्लैटफॉर्म इंडिया एक्ज़िम बैंक ने विकसित किया है। इस "नेत्र" पर आयडियाज़ के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के बारे में तमाम जानकारियों के साथ-साथ उनके रियल-टाइम अपडेट मिलेंगे। साथ ही, परियोजनाओं की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए उन्हें तीव्र गति से पूरा किया जा सकेगा। "नेत्र" प्लैटफॉर्म पर 200 से ज्यादा डेटा पॉइंट कैप्चर किए जा सकते हैं, ताकि भारत सरकार द्वारा रियायती ऋण-व्यवस्था की घोषणा करने से लेकर अनुमोदन प्रक्रिया की निगरानी और परियोजना के क्रियान्वयन तक हर चरण की जानकारी सुलभ हो सके। संशोधित आयडियाज़ दिशानिर्देशों और मॉडल दस्तावेजों के साथ-साथ यह "नेत्र" प्लैटफॉर्म भारत के लिए विकास सहयोग के नए युग का अगुआ होगा। ■

विभिन्न देशों का आर्थिक परिदृश्य

इटली

इटली अपने ऊर्जा आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। इसीलिए पूर्वी यूरोप के बाहर, यूक्रेन संकट के कारण बुरी तरह से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में से इटली भी एक हो सकता है। इसकी उम्मीद है कि यूरोपीय संघ के रिकवरी फंड की मदद से, यूक्रेन संघर्ष से पैदा हुई विकास बाधाओं को कुछ हद तक ठीक कर लिया जाएगा। इस तरह इटली की आर्थिक गतिविधि, 2021 की 6.6% की तुलना में 2022 में 2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। आयात किए जाने वाले तेल और गैस पर इटली की भारी निर्भरता है, जिसमें रूस का निर्यात भी शामिल है और अपेक्षाकृत बड़े पारंपरिक विनिर्माण क्षेत्र, जो अधिक ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, इन सबको देखते हुए यूरोपीय संघ में चल रही वैश्विक ऊर्जा मूल्य बढ़ोतरी से इटली की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक प्रभावित हुई है। साल 2022 में, औसत मुद्रास्फीति 6.3% तक पहुंचने की संभावना है। वहीं 2022 में डॉलर के मुकाबले यूरो आंशिक रूप से ठीक होगा, क्योंकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने 1 यूरो बनाम 1.10 डॉलर के अपेक्षित औसत के साथ ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही, 2022 के सकल घरेलू उत्पाद में इटली का चालू खाता अधिशेष घटकर 1.5% तक रहने का अनुमान है। यह 2021 में 2.5% रहा। ऐसा ऊर्जा की ऊंची कीमतों की वजह से व्यापार अधिशेष में गिरावट आने के कारण हुआ।

ट्यूनीशिया

महामारी और वैश्विक भू-राजनैतिक स्थिति की वजह से लगातार होने वाली अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए 2022 में ट्यूनीशिया की अर्थव्यवस्था में धीमी गति से सुधार होने की उम्मीद है। इसका असर पर्यटन क्षेत्र और उद्योग पर भी पड़ सकता। इससे, 2022 में अर्थव्यवस्था 2% की दर से ही बढ़ने की उम्मीद है। जबकि 2021 में यह 3.3% की दर से बढ़ी थी। संभावना है कि भोजन और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि की वजह से ट्यूनीशिया के आयात बिल में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि, सरकारी खर्च बढ़ाने का दबाव हो सकता है और राजनौतिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन संघर्ष के बाद गेहूं जैसे मुख्य उपभोक्ता उत्पाद की कमी के साथ ही, वैश्विक तेल और खाद्य कीमतों में उछाल की वजह से कीमतें बढ़ने का दबाव बना रह सकता है। इससे 2022 में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति बढ़कर 8.5% हो सकती है, जो 2021 में 5.7% रही है। यूएस डॉलर के मुकाबले ट्यूनीशियाई दीनार कमजोर हो सकता है, क्योंकि बड़े बाहरी असंतुलन से मुद्रा पर दबाव पड़ता है। इससे 2022 में मुद्रास्फीति भी बढ़ सकती है। वर्ष 2022 में औसतन 1 यूएस डॉलर का मूल्य 3.3 ट्यूनीशियाई दीनार रह सकता है, जो 2021 में 3.2 ट्यूनीशियाई दीनार रहा था।

इक्वाडोर

वर्ष 2021 में 4.2% की दर की वृद्धि के बाद, 2022 में इक्वाडोर की वास्तविक जीडीपी 2.1% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। साल 2023-26 के दौरान, आर्थिक वृद्धि औसतन 2% प्रति वर्ष से कम रहने की संभावना है। इसमें निजी खपत और निवेश का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। लंबे समय से चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष तथा मुद्रास्फीति के बढ़ने के चलते वृद्धि के लिए जोखिम बना हुआ है। साल 2022 में औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति बढ़कर 3.8% होने की आशंका है, क्योंकि खाद्य और वस्तुओं की वैश्विक कीमतें रूस-यूक्रेन संघर्ष की वजह से लगातार बढ़ रही हैं। वर्ष 2023-26 के दौरन मुद्रास्फीति औसतन 2.3% प्रति वर्ष हो सकती है, जो कि 2010-19 की तुलना में थोड़ी मंदी है। वर्ष 2022-26 के दौरान डॉलर के मजबूत बने रहने की उम्मीद है। डॉलर का कमजोर होना तकरीबन नामुमकिन राजनैतिक कयास है, क्योंकि व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के आधार पर डॉलर को विनिमय-दर व्यवस्था के लिए जरूरी माना गया है। आने वाले वर्षों में चालू खाते में अधिशेष बने रहने की उम्मीद है। निर्यात में निरंतर वृद्धि, तेल की ऊंची कीमतों और आयात वृद्धि में मंदी से 2022 में व्यापार अधिशेष बढ़ने की संभावना है। इससे सकल घरेलू उत्पाद में बाहरी अधिशेष 5.9% तक बढ़ने में मदद मिल सकती है।

सिंगापुर

कोरोना संक्रमण के बाद की अवधि में अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.6% की बढ़त देखने के बाद, उम्मीद है कि 2022 में सिंगापुर की अर्थव्यवस्था के 3.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। 2022 में बाहरी क्षेत्र के प्रदर्शन में इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों का उल्लेखनीय योगदान रह सकता है। संभावना है कि वैश्विक खाद्य और सामान की कीमतों में वृद्धि के चलते मुद्रास्फीति 2021 की 2.3% की तुलना में 2022 में तेजी से बढ़ते हुए 6% तक रह सकती है। सिंगापुर अलग-अलग मुद्राओं में व्यापार करने के साथ-साथ प्रबंधित विनिमय-दर व्यवस्था का इस्तेमाल करता है। सिंगापुर का मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस), 2024 तक अपनी मौद्रिक नीति में सख्त रुख बनाए रख सकता है। अमेरिकी ब्याज दर में बढ़ोतरी के बीच, स्थानीय मुद्रा को 2024 तक यूएस डॉलर के मुकाबले मामूली घाटे वाले दबाव का सामना करना पड़ सकता है। मुद्रा की विनिमय दर, 2022 के आखिर तक 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 1.38 सिंगापुर डॉलर तक पहुंच सकती है। पारंपरिक तौर पर, सिंगापुर अपने चालू खाते में अधिशेष रखता है। आने वाले वर्षों में भी यह अधिशेष बड़े पैमाने पर बना रह सकता है। वर्ष 2021 में चालू खाता शेष सकल घरेलू उत्पाद का 18.1% रहा। यह 2022 में बढ़कर 18.3% होने की उम्मीद है। निवल प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह में धनात्मक बढ़त बने रहने की संभावना है, क्योंकि विदेशी निवेशकों का सिंगापुर और दक्षिण-पूर्वी एशिया में आर्थिक संभावनाओं के बारे में सकारात्मक रुख बना हुआ है। ■

मुद्राओं की स्थिति

यूरो

€ अप्रैल महीने के आखिर के बाद से जून के दूसरे सप्ताह में यूरो ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपना अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। इस दौरान यूरो/यूएस डॉलर के मुकाबले लगभग 5.72% गिर गया। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के मज़बूत हौसले के बावजूद ऐसा हुआ। उसने मौजूदा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। मासिक संपत्ति खरीद को खत्म किया। मुद्रास्फीति के अनुमानों में सुधार की घोषणा की।

हालांकि, केंद्रीय बैंक ने विकास अनुमानों को नीचे किया है। बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के मौद्रिक विश्लेषकों के सर्वे के अनुसार, यूरो वाले क्षेत्र इस साल मंदी से बच सकते हैं। इससे 2022 की दूसरी तिमाही के बाद विकास दर में तेजी आ सकती है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की वजह से 19 देशों में इस्तेमाल होने वाले यूरो पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। इस कारण मुख्य रूप से ईंधन और खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के कारण उपभोक्ता के विश्वास, घरों में निवेश और उन्हें खरीदने की शक्ति को कम कर दिया है।

15 जून, 2022 को यूएस डॉलर का मूल्य 1:1.0443 यूरो रहा.

तुर्की का लीरा

₺ तुर्की के केंद्रीय बैंक ने 21% की मुद्रास्फीति दर के बावजूद अपनी ब्याज दर को 15% से घटाकर 14% किया। इससे तुर्की का लीरा (टीआरवाई) दिसंबर 2021 के आखिर में, मौजूद समय के अपने सबसे निचले स्तर 18.3624 तक गिर गया। पिछले साल लीरा में 44% की गिरावट दर्ज की गई थी। केंद्रीय बैंक की आरक्षित निधि में भारी गिरावट की वजह से उभरते हुए बाजारों में इसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा। जून में, यूएस डॉलर के मुकाबले तुर्किश लीरा 17.3611 तक कमजोर हो गया और हाल के नुकसान ने इसे पिछले दिसंबर में दर्ज किए गए गिरावट के रिकॉर्ड स्तर पर वापस ला दिया। अचानक से मुद्रा में यह गिरावट तब हुई, जब पैसों से जुड़ी नीतियों में अनोखे निर्णयों के बीच तुर्की में मुद्रास्फीति 20 साल के सबसे ऊंचे स्तर 73% से अधिक हो गई है। बाहरी वित्तपोषण, बढ़ती मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति के और अधिक बढ़ने की आशंका, नाटो में पश्चिम देशों के साथ राजनैतिक अस्थिरता, और दीर्घ विकास को प्रभावित करने के लिए नीतिगत बदलावों के लिए तुर्की के केंद्रीय बैंक की असहाय स्थिति की वजह से लीरा पर दबाव बढ़ रहा है।

15 जून, 2022 को एक यूएस डॉलर के मुकाबले तुर्किश लीरा का मूल्य 1:17.2254 रहा।

मिस्र का पाऊंड

E£ मार्च 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद मिस्र के पाउंड में लगभग 16% की गिरावट आई। इस वजह से विदेशी निवेशकों का मुद्रा पर दबाव बढ़ा। मिस्र के निधि-बाजारों से अरबों डॉलर निकाले गए। तब मिस्र के केंद्रीय बैंक ने आधिकारिक विनिमय दर को ईजीपी (मिस्र का पाउंड) 15.70 से बदलकर ईजीपी 18.27 प्रति यूएस डॉलर पर निर्धारित किया, जो नवंबर 2020 से व्यापार के लिए निर्धारित की गई दर थी।

पाउंड में ऐसे समय में गिरावट आई है जब दुनिया भर में कई खाद्य आपूर्ति शृंखलाएं यूक्रेन पर आक्रमण की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। मिस्र दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा आयातक है, जो लगभग 85% गेहूं की आपूर्ति के लिए रूस और 73% सूरजमुखी के तेल की आपूर्ति के लिए यूक्रेन पर निर्भर है। मिस्र को रूसी और यूक्रेनी सैलानियों के बीच लोकप्रिय लाल सागर के इलाके वाले रिसॉर्ट्स से मिलने वाले पर्यटन राजस्व में भी नुकसान हुआ है। हालांकि मार्च में शुरू हुई अमेरिकी फेडरल रिजर्व दर में बढ़ोतरी और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले ही, मिस्र अपने स्थानीय और विदेशी उधार के लिए चालू खाते और बजट घाटे को कम करने और अपनी मुद्रा को कमजोर करने के दबाव को रोकने की कोशिश कर रहा था।

15 जून, 2022 को यूएस डॉलर का मूल्य 1:18.7400 ईजीपी रहा।

बांग्लादेश का टका

৳ बांग्लादेश सही तरीके से बाजार में पैठ बनाकर अपनी मुद्रा का प्रवाह प्रबंधित करता है, ताकि अपनी विनिमय दर को यूएस डॉलर के मुकाबले एक सीमा के अंदर स्थिर रख सके। कोरोना के मामलों में गिरावट के साथ दुनियाभर में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई, क्योंकि रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण आपूर्ति की लागत बढ़ गई। नतीजतन, यूएस डॉलर की मांग बढ़ी और दुनिया में कई अन्य मुद्राओं की तरह बांग्लादेशी टका भी कमजोर होने लगा। अप्रैल 2022 की शुरुआत के बाद से बांग्लादेश का टका यूएस डॉलर के मुकाबले 7.80% कमज़ोर हो गया।

यूक्रेन और रूस के साथ-साथ बांग्लादेश आसपास के देशों से प्रमुख रूप से उर्वरक, गेहूं, और खाद्य तेल का आयात करता है। इस वजह से, बांग्लादेश में अचानक इन वस्तुओं की बहुत अधिक कमी हो रही है। इसके अलावा, गैस और तेल बाजार भी इस संघर्ष से समान रूप से अस्थिर हो गए हैं। इससे आयात भुगतान बढ़ रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेशी मुद्रा बाजारों में स्थिरता बनी रहे, बांग्लादेश बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में बैंकिंग प्रणाली में अब तक 6 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक का निवेश किया है। हालांकि, मांग के मुकाबले आपूर्ति बहुत कम रही और बाद में आयात बिलों का निपटान, 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 92.5 टका की पूर्व निर्धारित कीमत से अधिक दरों पर किया गया था।

अब तक के सबसे ऊंचे स्तर को छूने के बाद, 15 जून, 2022 को बांग्लादेश के टका का मूल्य यूएस डॉलर के मुकाबले 1:93.85 रहा। ■

एक्ज़िम मित्र

भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय को विस्तार देने और भारतीय उद्यमियों के बीच व्यापार वित्त, ऋण बीमा और व्यापार से जुड़ी अन्य सूचनाओं के प्रसार की विषमता दूर करने के लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक ने एक पोर्टल शुरू किया है। इसके मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं। पहला- निर्यातों के लिए ऋण की उपलब्धता के संबंध में जानकारी मुहैया कराना। उसके लिए समग्र प्रयास करना। दूसरा- एक्ज़िम मित्र के जरिए इस तरह के प्रयास करना, जिनसे भारतीय उद्यमियों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी जिज्ञासाओं का समाधान हो। इनमें से कुछ नीचे दी गई हैं:

अगर मेरे पास निर्यात-आयात कोड (आईसी) नंबर है, तो क्या मुझे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नंबर की आवश्यकता है?

दिनांक 12.06.2017 को जारी किए गए डीजीएफटी ट्रेड नोटिस संख्या 09 के अनुसार, जीएसटी के लागू होने के साथ (अधिसूचित तारीख), जीएसटीआईएन का इस्तेमाल निम्नलिखित के लिए किया जाएगा :

- वस्तुओं के आयात पर आईजीएसटी का क्रेडिट फ्लो, और
- वस्तुओं के निर्यात के संबंध में आईजीएसटी की वापसी या छूट।

जीएसटी के तहत पंजीकृत की गई संख्या को जीएसटीआईएन कहते हैं। यह 15-अंकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड है। इसमें पैन नंबर के आगे राज्य कोड लगाया जाता है। जबकि पैन नंबर के पीछे व्यावसायिक कार्यक्षेत्र के 3 अंकों की जानकारी को जोड़ा जाता है।

जीएसटीआईएन का इस्तेमाल उपरोक्त कार्यों के लिए किया जाता है। इसलिए परिवर्तन के स्तर पर पहचान के लिए इसका बहुत महत्त्व है। इसे देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि आयातक/निर्यातक को सिर्फ वस्तुओं के आयात और निर्यात के समय जीएसटीआईएन का उल्लेख करने की आवश्यकता होगी। पैन स्तर का डेटा एकत्रीकरण, अपने-आप ही सिस्टम में हो जाएगा।

विस्तृत जानकारी के लिए, उनकी स्थानीय एसईजेड वेबसाइट देखी जा सकती हैं।

फैक्टरिंग सेवाओं के बारे में जानकारी

भारत में कुछ नामित संस्थान ही फैक्टरिंग सेवाएं देती हैं, उदाहरण के लिए -

- आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड
- एसबीआई ग्लोबल
- स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
- कैनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड
- ईसीजीसी इंडिया लिमिटेड

सहायता के लिए कोई भी उनसे संपर्क कर सकता है। इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा भारतीय निर्यातों को बढ़ावा देने और विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के अपने व्यापक उद्देश्य पर काम जारी रखने के लिए, वित्तीय वर्ष 2023 में सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए निर्यात फैक्टरिंग शुरू की जाएगी।

साइपरमेथ्रिन (10% ईसी) (एचएस कोड-380899910) के निर्यात के संबंध में जानकारी

साइपरमेथ्रिन, कैमेक्सिल के निर्यात संवर्धन परिषद के दायरे में आता है। कैमेक्सिल की स्थापना भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अलग-अलग देशों को निम्नलिखित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से की गई थी-

पैनल- I : डाई और डाई इंटरमीडिएट।

पैनल- II : कृषि रसायनों सहित आधारभूत अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन।

पैनल- III : कॉस्मेटिक, साबुन, प्रसाधन सामग्री, और गंध वाले तेल।

पैनल- IV : विशिष्टता वाले रसायन, ल्युब्रिकैंट और अरंडी का तेल।

लाइसेंस और दस्तावेजों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, केमेक्ससिल के मुख्यालय में संपर्क करें :

कैमेक्सिल- रसायन निर्यात संवर्धन परिषद
चौथी मंजिल, झांसी कैसल, 7, कूपरेज रोड,
डॉ. अंबेडकर स्टैच्यू चौक क्षेत्र, कोलाबा, मुंबई, महाराष्ट्र 400001
(022 2202 1288) chemexcil.in/head-offices

क्या लदान के बिल में चालान मूल्य का उल्लेख किया जाना चाहिए? एक ही संदर्भ में, इंपोर्ट जनरल मेनिफेस्ट और लदान के बिल में क्या अंतर है?

कई न्यूज़लेटर्स से मिली जानकारी के अनुसार, हम समझते हैं कि "सी कार्गो मेनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट" के तहत इलेक्ट्रॉनिक मेनिफेस्ट जमा करते समय, ऐसी कई सूचनाएं हैं जिनकी जानकारी दी जानी चाहिए। धारा 1.6.4 के तहत सूचनाओं का एक समूह लदान बिल की जानकारी से संबंधित है और इसमें एक ऐसी धारा (1.6.4.38) शामिल है जो माल के चालान मूल्य के बारे में बताती है।

वाहकों को अब कार्गो के चालान मूल्य की जानकारी देने वाले लदान बिल जारी करने चाहिए। यह संभावित कानूनी प्रभाव के साथ मूल्यानुसार लदान बिल देगा कि वाहक को पैकेज/वजन सीमा के लिए छूट मिली हुई है।

हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि वर्तमान में, चालान मूल्य के प्रावधान को सीमा शुल्क प्राधिकरण वैकल्पिक मान रहा है। इसके अलावा, भारतीय समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम में अनिवार्य रूप से मूल्यानुसार लदान बिल जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है।

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र (विशेष रूप से सौर ऊर्जा संचालित उपकरण) में निर्यात संवर्धन परिषदों के बारे में जानकारी

नैशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनएसईएफआई) सभी भारतीय सौर व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यापक संगठन है। एनएसईएफआई ने भारत से अक्षय ऊर्जा उपकरणों और संबंधित सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) की तर्ज पर एक "नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात संवर्धन परिषद" बनाने की पेशकश की है। इसके अलावा, कई अन्य निर्यात संवर्धन परिषदें भी हैं, जो उपयोगी हो सकती हैं- सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद, और अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद।

आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था

वाणिज्यिक वस्तु व्यापार

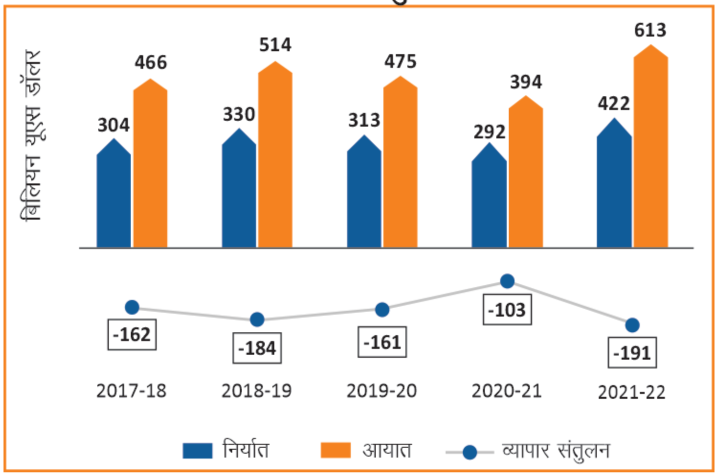

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सेवा क्षेत्र में व्यापार

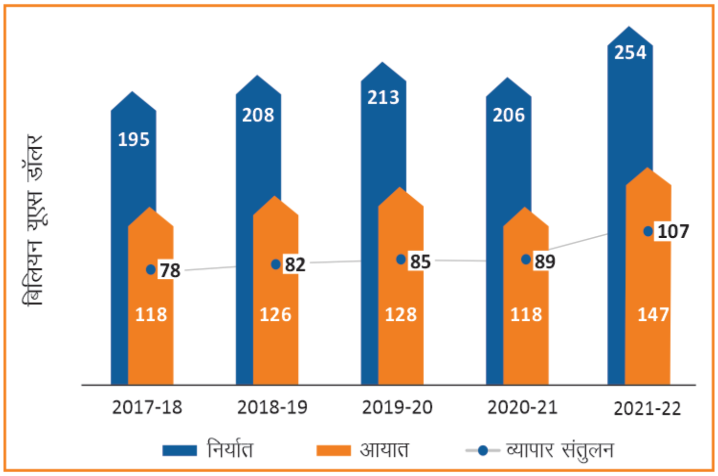

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह

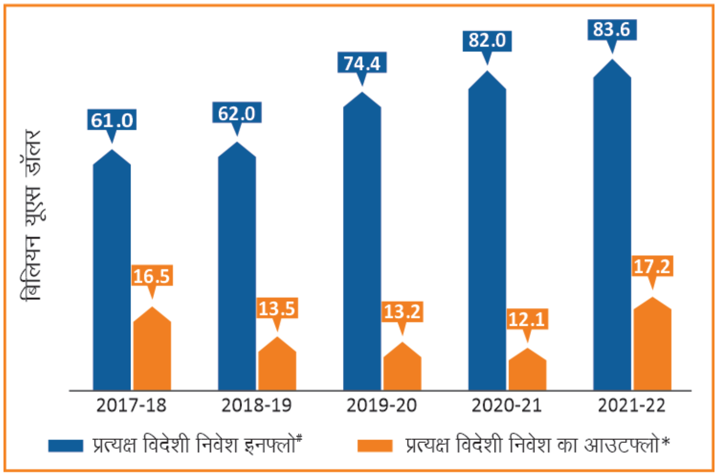

*नोट: *प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-बहिर्वाह के वास्तविक आंकड़ों में इक्विटी, लोन और गारंटियां शामिल हैं।*
#प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-इनफ्लो में इक्विटी, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल है।
स्रोत: आरबीआई और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

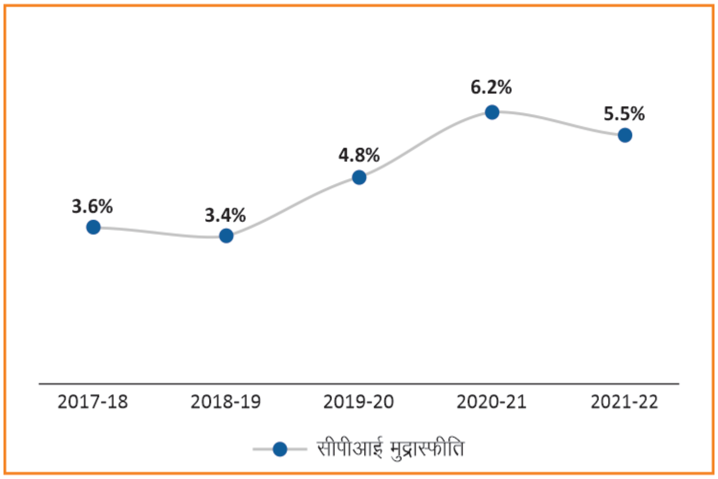

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चालू खाते का घाटा

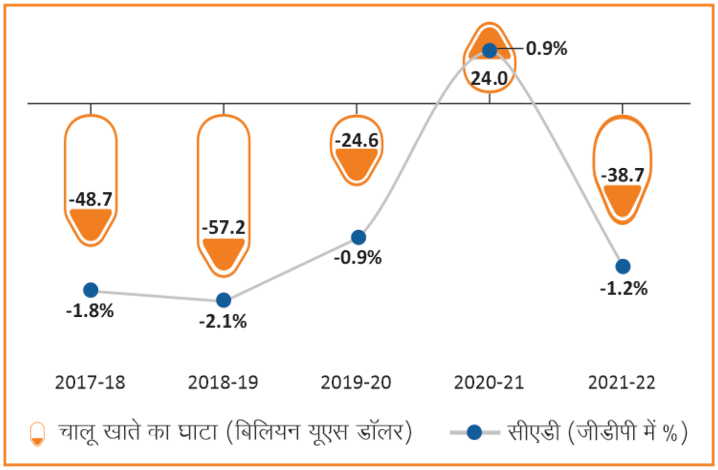

स्रोत: आरबीआई

क्षेत्रवार उत्पादन

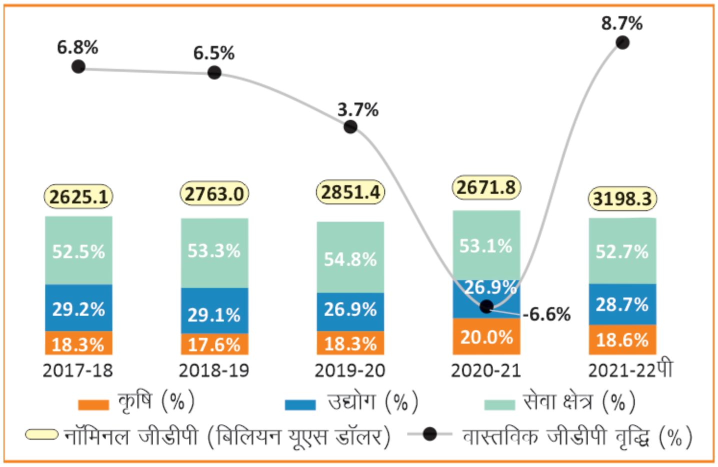

नोट: सांकेतिक जीडीपी (बिलियन यूएस डॉलर); पी-अनुमानित
स्रोत: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और एमओएसपीआई, भारत सरकार